

विचार बिन्दु

चापलूसी तीन घण्टियाँ दुर्गुणों से बही है—असत्य, दासत्व और विश्वासघात। —अन्जान

सरकार का एक ही काम, उलझाओ सुबह और शाम

2

014 जून में जब प्रधानमंत्री नंदें मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो एक आशा जगी थी कि सरकारी कामकाज में सलालीकरण होगा तथा जिता को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उन्होंने कई बार सार्वजनिक सभाओं में यह कहा कि उनका उद्देश्य श्रेष्ठ शासन और न्यूनतम सरकार का रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि सरकारी कार्यालयों के द्वारा आम अनुरक्षिकों के काम के बीच भी अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार स्थान यांत्रिकीय के लिए उनके लिए नहीं लगाए जाएंगे ताकि वे अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार स्थान यांत्रिकीय के लिए उनके लिए नहीं लगाए जाएंगे।

भाजपा सरकार के 11 वर्ष के बाद, होना तो ऐसा चाहिए था कि नागरिकों के सभी काम सलाला से होता है। उसके जीवन में आने वाली सरकारी उलझाने सुलझाने चाहिए थे। आज की स्थिति को देखें तो लगता है कि समाज या नागरिकों के प्रत्येक काम जैसे जन्म प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, छात्रवृत्ति के लिए सरकारी योजना का लाभ लेना हो, अयुष्मान योजना में लाभ करना हो, नया उद्यम प्रारंभ करना हो, भर्ती परीक्षा में भाग लेना हो, अपने मकान का नक्शा आपका सकराना हो, लाइसेंस लेना हो, हां काम में नागरिकों के लिए उनके पहले को अपराध बहुत बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों में प्रधानाचार और परेशनियां नहीं थीं, किंतु इस सरकार ने उन्हें दूर करने के बाद जिक्र या इसलिए इससे अपेक्षा भी बहुत अधिक बढ़ गई थीं। इस आलोखने में हम यह विवेषण उन्हें अपेक्षाओं के संरक्षण में करेंगे।

डिजिटाइजेशन, जिसे हर समस्या के हल के रूप में सरकार द्वारा लाया गया, उसने अधिकांश गरीब लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी, क्योंकि वे इस प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम ही नहीं हैं। इस धरातलीय तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण उपयुक्त होंगे।

सरकार ने फौजी राशन काढ़ धारकों के नाम होने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया। सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई नहीं हो सकता। कुछ समय बाद वह रेस्टर्या गया कि मजदूरों को वाले, घरों पर बताने साकर करने के लिए उनकी उंगलियों के नियम मिट जाने से उनके बायोमे�ट्रिक निशान रिकॉर्ड से मिलान नहीं होते थे। इस आधार पर उन्हें फौजी मानकर उनका राशन बंद कर दिया गया। ऐसे पुनः जारी करवाने की प्रक्रिया में कई सामाजिक संस्थाओं को अत्यंत परेशनियां का सामना करना पड़ा। जो निधन व्यवस्था के लिए उन्हें अपेक्षा भी बहुत अधिक बढ़ गई थीं। इस आलोखने में हम यह वर्चिलेषण उन्हें अपेक्षाओं के संरक्षण में करेंगे।

समान्यांश, रामोगी शेत्रों में अथवा शहरी जीवन की वसिताओं में फौंफ़ भरते समय नाम के अक्षरों में कमी-कमार को छोटी-मोटी गलती हो जाया करती है। अब ऐसा होने पर, वे किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश योजनाओं की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, हमारे यहां काम करने वाले एक व्यक्ति के पिता का नाम एक दस्तावेज़ में 'विजय कुमार' लिखा हुआ था और किसी दूसरे में 'की' के लिखा हुआ था। इस कारण उनका अधिकार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया और वे सभी योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए, जबकि उनकी अच्छी सारी सूचनाएं अब अविद्या अंतर्नालिन हैं। यह 'कुछ नहीं' अधिकारियों की सेवा पूँजी होती है।

इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानाचार कम होने की बजाय चाहे—अच्छाहे, जाने-अनजाने, पहले से अधिक बढ़ गया है। इसके काले भी इस पर निर्भर करते हैं कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति को बहुत अच्छी योजना भारत सरकार की है। इस योजना के अंतर्गत बहुत ही कम बच्चों को लाभ मिलता रहा है तथा वे अधिकांश योजनाओं की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, हमारे यहां काम करने वाले एक व्यक्ति के पिता का नाम एक दस्तावेज़ में 'विजय कुमार' लिखा हुआ था और किसी दूसरे में 'की' के लिखा हुआ था। इस कारण उनका अधिकार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया और वे सभी योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए, जबकि उनकी अच्छी सारी सूचनाएं अब अविद्या अंतर्नालिन हैं। यह 'कुछ नहीं' अधिकारियों की सेवा पूँजी होती है।

इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानाचार कम होने की बजाय चाहे—अच्छाहे, जाने-अनजाने, पहले से अधिक बढ़ गया है। इसके काले भी इस पर निर्भर करते हैं कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

आज स्थिति यह हो गई है कि बिना आवश्यक दस्तावेज़ के, आपको वंचित प्रमाण पत्र मिल

डिजिटाइजेशन, जिसे हर समस्या के हल

के रूप में सरकार द्वारा लाया गया, उसने अधिकांश गरीब लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी, क्योंकि वे इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए उनके सक्षम ही नहीं हैं। सरकारी कार्यालयों के लिए उनके लिए कुछ उदाहरण उपयुक्त होंगे।

पत्र कमी और स्वीकृत नहीं होती। जब कमी को उनके लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी रिपोर्ट भी इस पर निर्भर करती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

यही स्थिति संस्थाओं के पंजीकरण के लिए उनके लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

किसी योजना की होती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

जितने भी आदेश सरकार ने जारी किए, उनसे जटिलता और बढ़ गई है। इस धरातलीय तथ्य को प्रमाणित करने के लिए

कुछ उदाहरण उपयुक्त होंगे।

पत्र कमी और स्वीकृत नहीं होती। जब कमी को उनके लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

रिपोर्ट भी इस पर निर्भर करती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

यही स्थिति संस्थाओं के पंजीकरण के लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

किसी योजना की होती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

पत्र कमी और स्वीकृत नहीं होती। जब कमी को उनके लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

रिपोर्ट भी इस पर निर्भर करती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

यही स्थिति संस्थाओं के पंजीकरण के लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

किसी योजना की होती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

पत्र कमी और स्वीकृत नहीं होती। जब कमी को उनके लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

रिपोर्ट भी इस पर निर्भर करती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

यही स्थिति संस्थाओं के पंजीकरण के लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

किसी योजना की होती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

पत्र कमी और स्वीकृत नहीं होती। जब कमी को उनके लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

रिपोर्ट भी इस पर निर्भर करती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

यही स्थिति संस्थाओं के पंजीकरण के लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

किसी योजना की होती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

पत्र कमी और स्वीकृत नहीं होती। जब कमी को उनके लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

रिपोर्ट भी इस पर निर्भर करती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

यही स्थिति संस्थाओं के पंजीकरण के लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

किसी योजना की होती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

पत्र कमी और स्वीकृत नहीं होती। जब कमी को उनके लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

रिपोर्ट भी इस पर निर्भर करती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

यही स्थिति संस्थाओं के पंजीकरण के लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

किसी योजना की होती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

पत्र कमी और स्वीकृत नहीं होती। जब कमी को उनके लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

रिपोर्ट भी इस पर निर्भर करती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

यही स्थिति संस्थाओं के पंजीकरण के लिए उनकी नियरेक्षा के लिए आता है, तो उसकी

किसी योजना की होती है कि उसकी किसी योजना पैदा कर देती है।

पत्र कमी और स्वीकृत नहीं होती। जब कमी को उनके लिए उनकी नियरेक

